

लोकसभा के लिए
चुने गए विधायकों के
इस्तीफे की घोषणा



दोपहर संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नावेंकर ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए सात विधायकों के इस्तीफे की घोषणा बृहस्पतिवार को की। हाल में संपन्न आम चुनाव में कांग्रेस की प्रणति शिंदे, प्रतिभा धानोरकर, बलवंत वानखेडे और वर्षा गायकवाड, शिवसेना के रवींद्र वायकर और संदीपन भूमरे तथा राकांपा(शरद पवार) के नीलेश लांके ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के राजू परवे ने रामटेक संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले ही विधायक पद छोड़ दिया था। परवे हालांकि चुनाव हार गये थे। विधानसभा में दिवंगत सदस्यों मीनाक्षी पाटिल, पांडुरंग पाटिल, प्रतापराव भोसले, गंगाधर गाडे, त्रिम्बक कांबळे, डेमिनिक गोसावलेज और दगाडू गलांडे को श्रद्धांजलि दी गई।

दो बजे दोपहर

मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, नासिक, पुणे से एक साथ प्रकाशित

पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पॉसिबिलिटी है

उद्धव का शिंदे सरकार पर तंज



► महायुति को बताया लीकेज सरकार
► अयोध्या और नीट मामले पर जमकर बरसे

विधानसभा के मानसून सत्र को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार का 'विदाई' सत्र भी बताया। उन्होंने मांग की कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कृषि कर्ज माफ किया जाए। इससे पहले, महा विकास आघाडी (एमवीए) के विधायकों ने विधानसभा परिसर में नीट परीक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। एमवीए में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) शामिल हैं।

अनमोल विचार पागलों की दुनिया में समझदार बने रहना अपने आप में पागलपन है : जीन जैक्स रूसो



ठाकरे ने क्या कहा ?

ठाकरे ने कहा, " हम (शिवसेना-यूबीटी) विधान परिषद चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगे क्योंकि 11 सीट हैं और प्रत्येक पार्टी (विपक्षी गठबंधन के घटक राकांपा (शरद पवार गुट), शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस) एक-एक सीट जीत सकती है। हमारे मत तय हैं। " उन्होंने अपने बयान के साथ 'क्रॉस वोटिंग' की संभावना को भी हवा दे दी है। हमें अपने समीकरण को सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे जीत दर्ज करूंगा, उसे बताने की जरूरत नहींहमारे पास संख्याबल है। " उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन को अपने विधायकों को एकजुट रखने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव अपना उम्मीदवार उतारेगी शिवसेना (यूबीटी)

11 सीट के लिए 12 जुलाई को द्विवार्षिक चुनाव

महाराष्ट्र विधानमंडल के उच्च सदन की 11 सीट के लिए 12 जुलाई को द्विवार्षिक चुनाव होंगे। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) में क्रमशः 2022 और 2023 में हुए विभाजन के बाद पहली बार महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए चुनाव हो रहे हैं।

27 जुलाई को समाप्त हो रहा है कार्यकाल

महाराष्ट्र विधान परिषद के 11 सदस्यों का छह वर्षीय कार्यकाल 27 जुलाई को समाप्त हो रहा है जिसकी वजह से इन सीट पर चुनाव कराना आवश्यक हो गया है। विधान परिषद का द्विवार्षिक चुनाव अक्टूबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले हो रहा है। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में इस समय 274 सदस्य हैं और विधान परिषद का चुनाव जीतने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को 23 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होगी। विधानसभा में राकांपा (अजित पवार गुट) के 41, एकनाथ शिंदे नीट शिवसेना के 40 और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 103 सदस्य हैं। सदन में कांग्रेस के 37, शिवसेना यूबीटी) के 13 और राकांपा (शरद पवार गुट) के 15 सदस्य हैं। राकांपा (शरद पवार गुट) पौसेंट एंड वर्कस पार्टी (पीडब्ल्यूपी) के नेता जयंत पाटिल का समर्थन करेंगे। 2022 में विधान परिषद के लिए चुनाव में कांग्रेस नेता चंद्रकांत इंडोरे को संख्याबल होने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा था जो संकेत करता है कि 'क्रॉस वोटिंग' हो सकती है।

मुंबई पुलिस ने ईडी की हस्तक्षेप याचिका का किया विरोध

दोपहर संवाददाता | मुंबई
मुंबई पुलिस ने बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस अर्जी का विरोध किया जिसमें पुलिस की महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में हुए कथित 25 हजार करोड़ रुपये के घोटाले की जांच बंद करने के लिए दायित्व रिपोर्ट के मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मूल प्रार्थमिकी दर्ज की थी और मौजूदा उप मुख्यमंत्री अजित पवार को बतौर आरोपी नामजद किया था लेकिन बाद में ईओडब्ल्यू ने कहा कि शीर्ष सहकारी बैंक को कथित घोटाले से कोई अनुचित नुकसान नहीं हुआ।

सितंबर 2020 में दाखिल की थी मामले को बंद करने की अर्जी

ईओडब्ल्यू ने बृहस्पतिवार को दाखिल लिखित जवाब में कहा कि ईडी द्वारा इसी तरह की हस्तक्षेप अर्जी पूर्व में सांसदों और विधायकों के मामले में दाखिल की गई थी जिसे विशेष अदालत खारिज कर चुकी है। उसने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने ईडी रिपोर्टों के आधार पर नर सिंघे से अर्जी दाखिल की है। कथित घोटाले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू ने सबसे पहले मामले को बंद करने की अर्जी सितंबर 2020 में दाखिल की थी जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन जांच एजेंसी ने अक्टूबर 2022 में अदालत को सूचित किया कि वह शिकायतकर्ता और ईडी द्वारा दाखिल आपत्ति अर्जी में उठाए गए बिंदुओं पर आगे की जांच कर रही है। इस साल मार्च में ईओडब्ल्यू ने यह कहते हुए फिर से मामले को बंद करने का अनुरोध किया कि "कथित धोखाधड़ी के कारण बैंक को कोई अनुचित नुकसान नहीं हुआ।" मामले को बंद करने के लिए दाखिल रिपोर्ट में कहा गया कि सहकारी आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त एक पूर्व न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि "कारखानों (चीनी मिलों) को दिए गए ऋणों के कारण बैंक को कोई अनुचित नुकसान नहीं हुआ।

किसानों को कर्जमुक्त की मांग पर विपक्ष का विधानमंडल की सीढ़ियों पर आंदोलन

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्षी विधायकों ने गुरुवार को विधानमंडल की सीढ़ियों पर बैठकर आंदोलन किया। आक्रामक विपक्षी विधायकों ने राज्य सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि शिंदे सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है।

सरकार के विरुद्ध नारेबाजी
मुंबई में विधानमंडल का वर्षाकालीन सत्र के शुरू होने से पहले ही विपक्षी विधायक विधानमंडल की सीढ़ियों पर जमा हो गए और राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ कमीशन पर ही ध्यान दे रही है, जबकि किसानों की हालत बंद से बदतर हो गई है। विधायकों ने किसानों को उबारने के लिए उनका पूरा कर्ज माफ करने की मांग की। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय बडेड्वीवार और विधानपरिषद के नेता प्रतिपक्ष अंबादान दानवे ने कहा कि दोनों सदनो में विपक्ष किसानों की कर्जमाफी की मांग जोरदार तरीके से उठाएगा और सरकार से किसानों को कर्जमाफी की मांग करेगा।

व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या



पालघर। पालघर में चोर होने के संदेह में 23 वर्षीय एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर देने का सनसनी खेज मामला सामने आया है। पल्लार पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। मिली जानकारी के मुताबिक लोगों के एक समूह ने नालासोपारा के वेलाई पाडा इलाके में विजय उर्फ अभिषेक जोगिंदर सोनी को पकड़ लिया। लोगों को संदेह था कि विजय चोरी करने के इरादे से वहां घूम रहा है, इसलिए लोगों ने उसे लाटियों से बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया। फिलहाल मामले में अब तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

ठाकरे ने केंद्र तथा राज्य सरकार पर निशाना साधने के लिए नीट और राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के अयोध्या मंदिर में पानी के रिसाव के संबंध में हालिया बयान को लेकर पैदा विवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, " केंद्र और राज्य सरकार लीकेज सरकार हैं। परीक्षा का प्रश्नपत्र (नीट) लीक हुआ और राम मंदिर के गर्भगृह में पानी का रिसाव हुआ। उन्हें कोई शर्म नहीं आती। " पूर्व मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव से पहले कृषि कर्ज माफ करने की भी मांग की। उन्होंने कहा, "कृषि कर्ज तुरंत पूरी तरह माफ कर इसे राज्य में चुनाव से पहले लागू किया जाना चाहिए। " ठाकरे ने आरोप लगाया कि राज्य में पिछले दो वर्ष में 6,250 किसानों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि एक जनवरी से अब तक 1,046 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के लिए घोषित 10,020 करोड़ रुपये की सहायता अभी तक जारी नहीं की गयी है। शिवसेना (यूबीटी) नेता ने भाजपा नीट केंद्र सरकार पर देश में जल संकट को लेकर उदासीन होने का आरोप लगाया।

उद्धव बोले- सरकार को वादों पर लाना चाहिए श्वेत पत्र

शुक्रवार को पेश किए जाने वाले राज्य के बजट के मद्देनजर ठाकरे ने कहा कि बजट में " आश्वासनों की झड़ी " लगायी जाएगी लेकिन सरकार को उन वादों पर भी श्वेत पत्र लाना चाहिए जो उसने पिछले दो साल में पूरे किए हैं। मध्य प्रदेश की 'लाडली बहना' योजना की तर्ज पर राज्य में भी महिलाओं के लिए एक योजना शुरू किया जाने की खबरों पर ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में बढ़ती बेरोजगारी के मद्देनजर पुरुषों के लिए भी ऐसी ही पहल की जानी चाहिए। उन्होंने मराठी भाषी लोगों के लिए मुंबई में नयी आवासीय परियोजनाओं में 50 फीसदी मकान आरक्षित करने की मांग की। विधान परिषद सदस्य अनिल पारब की मांग का भी समर्थन किया। उन्होंने राज्य विधानसभा की इमारत की एक लिफ्ट में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात को " महज संयोग " बताया। इस मुलाकात की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। ठाकरे ने कहा कि यह " एक अनौपचारिक मुलाकात " थी। किए जाने की खबरों पर ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में बढ़ती बेरोजगारी के मद्देनजर पुरुषों के लिए भी ऐसी ही पहल की जानी चाहिए। उन्होंने मराठी भाषी लोगों के लिए मुंबई में नयी आवासीय परियोजनाओं में 50 फीसदी मकान आरक्षित करने की मांग की।

लिफ्ट में हुई फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात



हालांकि, शिवसेना-यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने इन कयासों पर विराम लगाते हुए कहा 'लोगों को 'ना' करना प्यार तुम्हीं से कर बैठे ' गीत याद आ रहा होगा लेकिन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ' ठाकरे ने आगे कहा कि लिफ्ट के कान नहीं होते और इस तरह की मुलाकात होना एक अच्छी बात है। यह एक अप्रत्याशित मुलाकात थी और इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।

भाजपा विधायक प्रवीण दारेकर ने क्या कहा?

जिस समय लिफ्ट में लिफ्ट में फडणवीस और ठाकरे की मुलाकात हुई, उस समय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक प्रवीण दारेकर भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने कहा कि लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही देवेंद्र फडणवीस सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यालय की ओर बढ़ गए और उद्धव ठाकरे विपक्षी पार्टी के कार्यालय की ओर चले गए। दारेकर ने कयासों पर विराम लगाते हुए कहा कि उद्धव का सत्तारूढ़ दल के साथ जुड़ने का कोई इरादा नहीं है।

भूमि सौदा संबंधी धनशोधन मामले खडसे ने खुद को आरोपमुक्त किए जाने का किया आग्रह

निर्णय तोरस्कर | मुंबई
विरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे ने पुणे जिले में 2016 के एक भूमि सौदे से संबंधित कथित धनशोधन मामले में बृहस्पतिवार को यहां एक विशेष अदालत में स्वयं को आरोपमुक्त किए जाने का आग्रह करते हुए याचिका दायर की। खडसे की पत्नी मंदकिनी खडसे और दामाद गिरीश चौधरी ने भी मामले में खुद को आरोपमुक्त किए जाने का आग्रह किया है। सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों को सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश आरएन रेकडे के समक्ष वकील स्विफिल अंबुरे द्वारा आवेदन दायर किए जाने के समय खडसे दंपति अदालत में उपस्थित थे।

ईडी से जवाब मांगा
तब पद छोड़ना पड़ा था जब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी पत्नी और दामाद के लिए पुणे के पास एक औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी भूमि की खरीद को सुविधाजनक बनाने के वारंते अपने पद का दुरुपयोग किया। ईडी ने आरोप लगाया है कि खडसे परिवार ने यह जमीन 3.75 करोड़ रुपये में खरीदी जबकि इसकी वास्तविक कीमत 31.01 करोड़ रुपये थी। भले ही खडसे और उनकी पत्नी को मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया है, लेकिन जांच एजेंसी ने उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया। खडसे के दामाद को जुलाई 2021 में गिरफ्तार किया गया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने से पहले वह दो साल से अधिक समय तक जेल में रहे।

मरीन ड्राइव पर पैर फिसलने से समुद्र में जा गिरी बुजुर्ग महिला



मुंबई। मुंबई के मरीन ड्राइव पर एक महिला की जान मुंबई पुलिस के जवान ने अपनी जान पर खेलकर बचाई। दरअसल, मरीन ड्राइव घूमने आई महिला पैर फिसलने से वह समुद्र में जा गिरी। इसके बाद मुंबई पुलिस कांस्टेबल ने बुजुर्ग महिला को बचाने के लिए समुद्र छलंग लगा दी। यह घटना गुरुवार को दोपहर करीब 2।45 बजे हुई, जब वह फिसलकर 20 फीट से अधिक नीचे पानी में गिर गई। वहां मौजूद लोगों के शोर मचाने के बाद मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन से जुड़े दो कांस्टेबल किरण ठाकरे और अनोल दहीफले ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत पानी में छलंग लगा दी, यहां तक कि अपनी जान को भी खतरे में डालने की परवाह नहीं की। दोनों कांस्टेबल ने रिंग, टायर और सुरक्षा रिसरों की मदद से तेजी से बचाव अभियान चलाया। महिला को बाहर निकाला गया और महिला पुलिस कांस्टेबलों द्वारा जीटी अस्पताल पहुंचाया गया। महिला की पहचान माटुंगा ईस्ट की निवासी स्वाति कनानी के रूप में हुई है, जिनका वर्तमान में एक नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह घटना सुंदर महल जंक्शन के पास हुई और बचाव अभियान लगभग 20 मिनट तक चला।

जुलाई में म्हाडा के मुंबई मंडल की लॉटरी

► करीब डेढ़ हजार मकानों का समावेश
► पिछली लॉटरी के बचे हुए 455 मकानों का भी समावेश
दीपक पवार | मुंबई



455 घर बचे
मुंबई में आम नागरिकों का सही घर का सपना पूरा करने वाली कंपनी म्हाडा के मुंबई बोर्ड ने अगले महीने हाउस लॉटरी निकालने की पहल शुरू कर दी है। इस लॉटरी में करीब 1 हजार 500 घर शामिल होंगे। म्हाडा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2023 में निकाली गई लॉटरी से बचे 455 घरों को इसमें शामिल किया जाएगा। म्हाडा के मुंबई डिवीजन के माध्यम से हर साल एक हाउस लॉटरी आयोजित की जाती है। लॉटरी पिछले साल अगस्त महीने में आयोजित की गई थी। इस लॉटरी को नागरिकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इस लॉटरी के सफल विजेताओं को मकानों का कब्जा दे दिया गया है। सिर्फ 200 लोगों को कब्जा लेना बाकी है। विजेताओं के जवाब न देने और आवेदकों के जवाब न देने के कारण इस लॉटरी में 455 घर बचे हैं। बोर्ड ने पिछली लॉटरी के बचे हुए मकानों और विभिन्न स्थानों पर बन रहे प्रोजेक्टों के मकानों की लॉटरी निकालने का काम जुलाई माह में शुरू कर दिया है। इस लॉटरी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की दो बैठकें हो चुकी हैं। घरों की सूची और कीमत को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है और इन घरों की लॉटरी जुलाई महीने में निकाली जाएगी। इस लॉटरी में गोरगांव, दक्षिण मुंबई, पवई, विक्रोली आदि के बिखरे हुए घर शामिल होंगे।

राष्ट्रपति का 50 मिनट का अभिभाषण : सेनाओं में सुधार का दावा, अग्निवीर का नाम नहीं

एजेंसी | नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को कहा कि सरकार पेपर लीक की घटनाओं की जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके साथ राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आपातकाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संविधान पर कई हमलों के बावजूद देश ने असंवैधानिक ताकतों पर विजय पाई है। 18वीं लोकसभा में पहली बार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पेपर लीक का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त उपाय कर रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सत्तापक्ष के सदस्य देर तक मेज थपथपाते दिखे, वहीं विपक्षी सदस्यों ने नीट-नीट के नारे लगाए। इससे सदन के अंदर शोर बढ़ गया और राष्ट्रपति को सदस्यों से अपनी बात सुनने के लिए आग्रह करना पड़ा। राष्ट्रपति के करीब 55 मिनट के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने करीब 180 बार मेजें थपथपायीं तो विपक्षी सदस्यों ने भी पलटवार का कोई मौका नहीं गंवाया। दोनों ने नारों से एक-दूसरे पर तंज भी कसे। मुर्मू ने कहा कि सरकारी भर्ती हो या परीक्षाएं, किसी भी कारण से इनमें रूकावट उचित नहीं है। इसमें शुचिता और पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कई राज्यों में भी पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर दलगत राजनीति से ऊपर उठने की भी नसीहत की।

सरकार पेपर लीक की जांच करेगी : राष्ट्रपति

'आपातकाल काला अध्याय'

राष्ट्रपति ने अभिभाषण के दौरान 1975 में लागू आपातकाल को संविधान पर सबसे बड़े हमला और काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि अनेक हमलों के बावजूद देश ने असंवैधानिक ताकतों पर विजय प्राप्त करके दिखाई है। भारत का संविधान बीते दशकों में हर कसौटी और चुनौती पर खरा उतरा है। उन्होंने कहा कि सरकार संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम नहीं मानती, बल्कि उसकी कोशिश है कि संविधान हमारी चेतना का हिस्सा बने। इस बीच विपक्ष ने इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराया।



'आधुनिक सैन्यबल जरूरी'

राष्ट्रपति ने कहा कि सशक्त भारत के लिए आधुनिक सैन्यबल जरूरी है। उन्होंने कहा कि युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ रहे, इसके लिए सेना में सुधार की प्रक्रिया लगातार जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सोच के साथ सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई सुधार किए हैं। राष्ट्रपति जब सैन्यबलों के आधुनिकीकरण का जिक्र कर रही थीं, उस वक्त विपक्षी सदस्यों ने अग्निवीर-अग्निवीर कहे हुए शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके जवाब में सत्तापक्ष के सदस्यों ने देर तक मेज थपथपाई, ताकि विपक्षी सदस्यों की आवाज सुनाई न दे।

'गलत सूचनाओं के प्रति आगाह'

मुर्मू ने सदस्यों को गलत सूचनाओं के बारे में आगाह करते हुए कहा कि संघर्ष काल के युग में विघटनकारी ताकतें, लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दारार डालने की साजिश रच रही हैं। यह ताकतें देश के भीतर और बाहर से भी संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को ऐसे ही बेरोकटोक नहीं चलने दिया जा सकता।

'आधुनिक सैन्यबल जरूरी'

राष्ट्रपति ने कहा कि सशक्त भारत के लिए आधुनिक सैन्यबल जरूरी है। उन्होंने कहा कि युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ रहे, इसके लिए सेना में सुधार की प्रक्रिया लगातार जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सोच के साथ सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई सुधार किए हैं। राष्ट्रपति जब सैन्यबलों के आधुनिकीकरण का जिक्र कर रही थीं, उस वक्त विपक्षी सदस्यों ने अग्निवीर-अग्निवीर कहे हुए शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके जवाब में सत्तापक्ष के सदस्यों ने देर तक मेज थपथपाई, ताकि विपक्षी सदस्यों की आवाज सुनाई न दे।

'गलत सूचनाओं के प्रति आगाह'

मुर्मू ने सदस्यों को गलत सूचनाओं के बारे में आगाह करते हुए कहा कि संघर्ष काल के युग में विघटनकारी ताकतें, लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दारार डालने की साजिश रच रही हैं। यह ताकतें देश के भीतर और बाहर से भी संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को ऐसे ही बेरोकटोक नहीं चलने दिया जा सकता।

आने वाला समय हरित युग

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आने वाला समय हरित युग का है। सरकार हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ा रही है। हरित ऊर्जा हो या फिर हरित मोबिलिटी, हम हर मोर्चे पर बड़े लक्ष्यों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अपने शहरों को रहने के लिहाज से बेहतरीन स्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

'पूर्वोत्तर को रणनीतिक गेटवे बनाने के लिए काम हो रहा'

अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए पिछले 10 वर्षों में आठ्वें में चार गुना से अधिक की वृद्धि की है और वह इस क्षेत्र को एक्ट ईस्ट नीति के तहत रणनीतिक गेटवे बनाने के लिए काम कर रही है। पूर्वोत्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

'रिकॉर्ड मतदान से कश्मीर के दुश्मनों को जवाब'

संसदीय चुनाव के दौरान जम्मू-कश्मीर में मतदान के कई रिकॉर्ड टूटने का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि घाटी ने देश के दुश्मनों को कराया जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अब भारत के भूभाग जम्मू-कश्मीर में भी संविधान पूरी तरह लागू हो गया है, जहां संविधान के अनुच्छेद 370 की वजह से स्थितियां कुछ और थीं।

70 साल से अधिक के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज

राष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार बड़ा निर्णय लेने जा रही है। उन्होंने कहा कि अब आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवा रही हैं।

सीए के तहत नागरिकता मिलना प्रारंभ

मुर्मू ने कहा कि सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीए) के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है और इससे अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है। उन्होंने कहा कि एक जुलाई से देश में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) भी लागू हो जाएगी। अब डंड की जगह न्याय की प्रार्थमिकता होगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार किसानों की खेती पर लागत कम करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की आपूर्ति शृंखला को सशक्त कर रही है। गांवों में कृषि आधारित उद्योगों, डेयरी और मत्स्य पालन आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है।

अभिभाषण की प्रति लोकसभा के पटल पर रखी गई

संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के संबोधन के बाद उनके अभिभाषण की प्रति लोकसभा के पटल पर रखी गई और फिर सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद निचले सदन की कार्यवाही आरंभ हुई। इसके बाद बिरला ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा के कक्ष के उपयोग के लिए नियम में सुधार दिए जाने का उल्लेख किया। फिर उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने के बारे में सदन को सूचित किया।

आईआईटी, आईआईएम की संख्या बढ़ाने के प्रयास

मुर्मू ने कहा कि सरकार आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे प्रतिष्ठानों को मजबूत करने और उनकी संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है। विगत 10 वर्षों में देश में सात नए आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 नए एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।

सुधारों की गति तेज करेगा बजट

राष्ट्रपति ने कहा कि नवगठित एनडीए सरकार का पहला बजट कई ऐतिहासिक कदम उठाने के साथ आर्थिक सुधारों की गति को तेज करेगा और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार की दूरगामी नीतियों की रूपरेखा पेश करेगा।

भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है और पिछले 10 साल में उड़ान मार्गों में वृद्धि से द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों को कायदा हुआ है। अप्रैल 2014 में केवल 209 विमानन मार्ग थे, जो अप्रैल 2024 तक बढ़कर 605 हो गए।

बुलेट ट्रेन गलियारों के लिए अध्ययन का फैसला

मुर्मू ने कहा कि सरकार ने उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत में बुलेट ट्रेन गलियारों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करने का फैसला किया है। मेरी सरकार उन आधुनिक मानदंडों पर काम कर रही है, जिससे भारत विकसित देशों के सामने बराबरी से खड़ा हो सके।

महिलाओं का कौशल, कमाई के साधन बढ़े

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार चाहती है कि महिलाओं का कौशल, उनकी कमाई के साधन और उनका सम्मान बढ़े। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीते 10 वर्षों में बने चार करोड़ मकानों में से ज्यादातर मकान महिलाओं के नाम ही आवंटित हुए हैं। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ महिलाएं स्व-सहायता समूहों से जुड़ी हैं।

न्यून ब्रीफ

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन के लिए तैयार : दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़। जननायक जनता पार्टी (जजपा) के नेता दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को कहा कि राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार है। चौटाला ने हरियाणा में अगले विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में सत्तारूढ़ भाजपा के साथ गठबंधन की सभी संभावनाओं को सिर से खारिज कर दिया। भाजपा ने हरियाणा में मार्च में मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सेनी को मुख्यमंत्री बना दिया, जिसके बाद जजपा के साथ पिछले साढ़े चार वर्ष से जारी उसका गठबंधन टूट गया था। हाल में संपन्न हुए आम चुनावों में जजपा ने राज्य की सभी 10 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसे एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हट्टा के रोहतक लोकसभा सीट से विजयी होने के बाद संसद के उच्च सदन में यह सीट खाली हुई है।

तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर तैयारी जारी

एजेंसी | हैदराबाद

तेलंगाना ने तीन नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। तीन नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि इन नए कानूनों की अनुवाद प्रक्रिया भी चल रही है और इसके भी 1 जुलाई से पहले पूरी होने की उम्मीद है।

नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला यदियुरप्पा के खिलाफ आरोप पत्र दायर

एजेंसी | बेंगलुरु

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. यदियुरप्पा के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोपों की जांच कर रहे अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने पाँक्सों मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत में गुरुवार को आरोप-पत्र दायर किया। इस साल मार्च में सदाशिवनगर पुलिस ने भाजपा के वरिष्ठ नेता के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया था। इसके बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने इस मामले को आगे की जांच के लिए सीआईडी को सौंपने का आदेश जारी किया था।

दिल्ली में NTA के दफ्तर में घुसे NSUI कार्यकर्ता

एजेंसी | नई दिल्ली

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत में बुलेट ट्रेन गलियारों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करने का फैसला किया है। मेरी सरकार उन आधुनिक मानदंडों पर काम कर रही है, जिससे भारत विकसित देशों के सामने बराबरी से खड़ा हो सके।

गूगल इंडिया के खिलाफ दायर शिकायत खारिज

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल इंडिया के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया है, जिसमें कॉलर आईडी और स्पैम बचाव ऐप के बाजार में ट्रॉकर को लाभ पहुंचाने के लिए अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि गूगल की इस गतिविधि ने बाजार को विकृत कर दिया है और ट्रॉकर के लिए एकाधिकार की स्थिति पैदा हो गई है। दोनों की तरफ से रखी गई दलीलों की समीक्षा करने के बाद प्रतिस्पर्धा आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता के दावे निराधार थे।

लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए बनाई टीम

अधिकारी ने बताया कि अधिसूचना का मसौदा तैयार है और अगले कुछ दिनों में नए कानूनों को अधिसूचित कर दिया जाएगा। नए कानूनों को सरकार की योजना के अनुसार लागू किया जाए, इसके लिए विभिन्न स्तरों पर टीमों गठित की गई हैं। पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं और तेलंगाना राज्य पुलिस अकादमी में आईपीएस अधिकारियों के लिए नए आपराधिक कानूनों पर एक वर्कशॉप भी आयोजित की गई और उन्हें नए कानूनों की भावना के बारे में भी बताया गया। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रशिक्षित करने और सभी के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए विशेष टीम बनाई गई हैं। नए कानूनों के लिए अभियोगों की टीम ने एसओपी और दिशा-निर्देश तैयार किए हैं और उन्हें सभी फील्ड अधिकारियों के पास भेजा गया है।

कोर्ट ने लगाई थी यदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक

यदियुरप्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले महिला (54 वर्षीय) की फेफड़ों के कैंसर के कारण पिछले महीने यहां एक निजी अस्पताल में मौत हो गई थी। सीआईडी ने मामले में 17 जून को यदियुरप्पा से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की थी। इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस मामले में सीआईडी को यदियुरप्पा को गिरफ्तार करने के रोकने का आदेश दिया था।

कल्लाकुरुची जहरीली शराब त्रासदी: स्टालिन सरकार से की CBI जांच की मांग

भूख हड़ताल पर बैठे अन्नाद्रमुक विधायक

एजेंसी | चेन्नई

तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के नेताओं ने कल्लाकुरुची जहरीली शराब त्रासदी को लेकर राज्य सरकार द्रमक की निंदा की। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए अन्नाद्रमुक के कई नेता गुरुवार को भूख हड़ताल पर बैठ गए। दरअसल, जहरीली शराब पीने से अबतक 63 लोगों की मौत हो गई। अन्नाद्रमुक नेता एडप्पादी पलानीस्वामी समेत कई नेता इस भूख हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद अन्नाद्रमुक ने सदन में कल्लाकुरुची जहरीली शराब त्रासदी को लेकर हंगामा किया। उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच के साथ मुख्यमंत्री

लोस अध्यक्ष के आपातकाल पर प्रस्ताव से कांग्रेस नाखुश

एजेंसी | नई दिल्ली

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत में बुलेट ट्रेन गलियारों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करने का फैसला किया है। मेरी सरकार उन आधुनिक मानदंडों पर काम कर रही है, जिससे भारत विकसित देशों के सामने बराबरी से खड़ा हो सके।

आज कश्मीर पहुंचेगा अमरनाथ तीर्थयात्रियों का पहला जत्था

जम्मू। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था शुक्रवार को कश्मीर पहुंचेगा। यहां से वे उत्तर कश्मीर बालटाल और दक्षिण कश्मीर अनंतनागा बेस कैंप जाएंगे। शुक्रवार को सुरक्षा कर्तवियों के साथ सभी तीर्थयात्री घाटी के लिए रवाना होंगे और शनिवार (29 जून) को अमरनाथ के दर्शन करेंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत बुधवार से हो गई है। जम्मू के SDM ने बताया कि सरस्वती धाम सेंटर से के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष से आपातकाल पर पड़े प्रस्ताव पर नाखुशी जताते हुए कहा कि आसन से यह नहीं होना चाहिए था।

संसद सत्र कार्यवाही में ले सकेंगे हिस्सा, राज्यसभा सचिवालय ने किया ऐलान

संजय सिंह का 11 महीने बाद निलंबन खत्म

एजेंसी | नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का करीब 11 महीने का लंबा निलंबन 26 जून को खत्म कर दिया गया है। अब वह राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे। राज्यसभा सचिवालय ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। संजय सिंह को पिछले साल मानसून सत्र के दौरान 24 जुलाई को अमर्यादित आचरण के चलते सदन से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद मामले की जांच विशेषाधिकार समिति को सौंपी गई थी। राज्यसभा की तरफ से जारी बयान के अनुसार, विशेषाधिकार समिति ने 26 जून को इस मामले पर अपनी 77वीं तथा 78वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट में समिति ने संजय सिंह को विशेषाधिकार हनन का दोषी माना लेकिन यह भी कहा कि संजय सिंह पहले ही निलंबन के रूप में



इसकी पर्याप्त सजा पा चुके हैं। इसलिए उनका निलंबन खत्म कर दिया जाए। राज्यसभा के सभापति ने रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए संजय सिंह का निलंबन खत्म कर दिया। निलंबन खत्म होने पर संजय सिंह ने 'एक्स पर लिखा कि लगभग एक साल के बाद संसद में जाने की अनुमति मिली है। निलंबन खत्म हुआ। उन्होंने सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विशेषाधिकार समिति के सभापति और सभी सदस्यों का आभार जताया।

फर्जी हस्ताक्षर मामले में चार अधिकारियों पर गिरी गाज

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के चार अधिकारियों पर पूर्व वरिष्ठ अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर एक आदेश जारी करने का आरोप लगा है। इस संबंध में नव नियुक्त निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने संज्ञान लेते हुए भवन निर्माण विभाग के चारों अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निगम के कोरोनालबाग जोन के उपायुक्त पद पर वर्ष 2021 के दौरान आईएस अधिकारी हिमांशु गुप्ता कार्यरत थे। बुधवार को उनके फर्जी हस्ताक्षर कर एक आदेश जारी हुआ। मौजूदा समय में आईएस हिमांशु गुप्ता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के सचिव पद पर काम कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी सूचना भी लोगों को शिकायतों के जरिए प्राप्त हुई है कि जमीन के उपयोग मामले में जानबूझकर कुछ स्थानों पर निशाना बनाया जाता है।

बालटाल-अनंतनागा बेस कैंप में रुकेंगे यात्री, 29 जून को बाबा बर्फानी के करेंगे दर्शन

ऑफलाइन टोकन दिया जा रहा है। यात्रा की शुरुआत से पहले ही साधु-संत जम्मू पहुंचने लगे हैं।